(b) The number of trawlers belonging to sick/defaulting fishing companies, assisted by erstwhile SDFC/SCICI, operating from Visakhapatnam, is 88.

(c) The Government is aware of the problems of the sick deep sea fishing units at Visakhapatnam and had formulated a rehabilitation package in 1991, which was furher liberlised in 1992. Government has also constituted a Technical Committee to look into the problems of the sick deep sea fishing units and suggest remedial measures.

**Shrimp caught by deep-sea fisbing vessels**

1081. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) what are the figures of shrimp caught by Indian deep-sea fishing vessels in 1990-91,1991-92 and 1992-93;

(b) the approximate value of exports; thereof;

(c) whether there has been stagnation in terms of foreign exchange obtained from exports of shrimp caught by deep-sea fishing vessels; and

(d) if so of what are the reasons therefor :

THE MINISTER OF THE STATE OF THE MINISTRY OF FOOD RPOCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) : (a) While the figures of shrimp cauhgt by deep sea fishing vessels alone are not available, the shrimp production in India including the catch from the deep sea fishing vessels during 1990-91, 1991-92 and 1992-93 are given below :

| Year | Production (M.T.) |
|---|---|
| 1990-91 . . . | 2,73,028 |
| 1991-92 . . . | 3,22,034 |
| 1992-93 . . . | 3,53,580 |

(b) The value of export of marine products including the value of export from the deep sea fishing vessels during the 3 years is as follows :

| Year | Quantity (tons). | Value (Rs. crores). |
|---|---|---|
| 1990-91 | 139419 | 893.37 |
| 1991-92 | 171820 | 1375.89 |
| 1992-93 | 208600 | 1767.43 |

(c) There was no stagnation in terms of foreign exchange obtained from export of marine products from India. There was positive growth rate every year, which was 40.7%, 54% and 28.5% during 1990-91. 1991-92 and 1992-93.

(d) Does not arise.

**बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रवेश की अनुमति प्रदान करना**

**1082. चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कम्पनियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है और भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों का प्रतिशत कितना-कितना है; और

(ग) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में श्रम प्रधान उद्योग को प्राथमिकता प्रदान करने पर विचार कर रही है ताकि इससे भारत में बढ़ती बेरोजगारी को रोका जा सके ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गयी है। विदेशी/अनिवासी भारतीय पूंजी-निवेश वाली खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियों को अपने उत्पाद के विपणन क लिए विद्यमान और भावी घरेलू उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा करनी होती है। मंत्रालय को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि इसके कारण भारतीय कम्पनियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है :

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं अत: सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या और इनमें कार्यरत लोगों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) रोजगार पैदा करने, मूल्य वर्धन और निर्यात की संभावना को समझते हुए सरकार ने खाद्य प्रसस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें भी तैयार की हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है।

**Expert Committee on Food Processing Sector**

1083. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether Government had set up an Expert Committee in the food processing sector to help the Government in formulating its policy;

(b) if so, whether the expert committee had submitted reports to Government; and

(c) if so, the details of changes now Govern" ment propose to make in its food processing policy ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) :

(a) to (c) An Expert Committee has been set up to study the existing status of Food Processing Industries in the North-East em States and to suggest long-term ana short-term action plans for development of food Processing Industries there. The Committe is expected to submit its Repor shortly.

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के के लिए प्राप्त हुए ज्ञापन**

1084. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1991 से मार्च, 1993 तक की अवधि के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की इकाईयों को स्थापित करने के लिए 2042 औद्योगिक उद्यम संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी इकाईयों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या शेष इकाईयों के संबध में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितने प्रस्तावों को रद्द किया गया है तथा कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ङ) प्रस्तावों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या यह सच है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की सभावना है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने क लिए निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं ?